



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1971/वैशाख 7, 1893

No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1971/VAISAKHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April 1971

No. 3/14/71-AIS(IV).—In the following notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. No.3/15/66-AIS(IV), dated 19th May, 1967
2. No. 3/18/67-AIS(IV), dated 14th November, 1967
3. No. 3/18/67-AIS(IV), dated 26th March, 1968
4. No. 3/52/67-AIS(IV), dated 29th May, 1968
5. No. 3/21/68-AIS(IV), dated 26th November, 1968
6. No. 3/21/68-AIS(IV), dated 11th March, 1969

the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the Madhya Pradesh Cadre of the Indian Forest Service with effect from 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the

decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointments of the officers named in the aforesaid notifications to the Indian Forest Service have been rendered *ab initio* void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

सं० 3/14/71-अ० भा० से (4).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, अर्थात् —

1. सं० 3/15/66-अ० भा० से (4) दिनांक 19-5-1967
2. सं० 3/18/67-अ० भा० से (4), दिनांक 14-11-1967
3. सं० 3/18/67-अ० भा० से (4), दिनांक 26-3-1968
4. सं० 3/52/67-अ० भा० से (4), दिनांक 29-5-1968
5. सं० 3/21/68-अ० भा० से (4), दिनांक 26-11-1968
6. सं० 3/21/68-अ० भा० से (4), दिनांक 11-3-1969

भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन भर्ती किये गये अधिकारियों को जिन के नाम उनमें दिये गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में पहली अक्टूबर, 1966 से नियुक्त किया था अब सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1967 की रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम न्यायालय में 1970 की विशेष अवकाश याचिकाओं सं० 766/70 और 1574 से 1578 तक में भारत के, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आये अधिकारियों के नामों की नियुक्तियां प्रारंभ से ही अमान्य घोषित की गई है। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन नयी भर्ती करने के लिए आगे कार्रवाई करने का है।

No. 3/15/71-AIS(IV).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs' No. 3/19/66-AIS(IV), dated the 2nd February, 1967, the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the Maharashtra Cadre of the Indian Forest Service with effect from the 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointments of the officers named in the aforesaid notification to the Indian Forest Service have been rendered *ab initio* void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

सं० 3/15/71-प्र०भा०से(4).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3/19/66-प्र०भा०से(4) दिनांक 2 फरवरी, 1967 में भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन भर्ती किये गये अधिकारियों को जिन के नाम उनमें दिए गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में पहली अक्टूबर, 1966 से नियुक्त किया था अब सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1967 की रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम न्यायालय में 1970 की विशेष अवकाश याचिकाओं सं० 766/70 और 1574 से 1578 तक में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आये अधिकारियों के नामों की नियुक्तियां प्रांभ से ही अमान्य घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम उप नियम (1) के अधीन नयी भर्ती करने के लिए, आगे कारवाई करने का है।

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

